

स्वातंत्र बोल

RNI : CHHHIN 2022/86325

www.swatantrabol.com

विदेशी फंडिंग से हो रहा
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण...



छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012

एक बेहद **सख्त** कानून है।
इस कानून में **मृत्युदंड** तक का प्रावधान है।

इस कानून के तहत अपराध है :-

- बच्चों का लैंगिक शोषण करना या करवाना
- लैंगिक शोषण का प्रयास करना या करवाना
- अश्लील साहित्य हेतु बच्चों का उपयोग करना या करवाना

**चाईल्ड हेल्पलाइन
1098**



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा
बाल हित में प्रसारित

- निवेदन -

स्वतंत्र बोल से संबंधित कोई भी झुझाव या शिकायत हो तो आप नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। फोन और ई-मेल पर भी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र से घटित कोई घटना, समाचार, या अन्य कोई गतिविधि जो पत्रिका में प्रकाशन योग्य हो.. तो उससे भी भेज सकते हैं।

छत्तीसगढ़ का सबसे विश्वसनीय हिन्दी मासिक पत्रिका
तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल और न्यूज वेबसाइट को निर्भीक और
जनपक्षीय पत्रकारिता के लिये आर्थिक रूप से सहयोग करें।

बंधन बैंक

बैंक खाता नंबर - 20100031810292
आईएफएससी कोड - BDBL0001958



संपादक स्वतंत्र बोल

डी-317 बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)

97543-74333, bolswatantra@gmail.com



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



सुशासन
तिहार 2026



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सुशासन तिहार

2026

01 मई
से
10 जून
2026

**गाँव-गाँव, द्वार-द्वार
सुशासन की सरकार**



जिला स्तर पर लंबित प्रकरणों, जमीन संबंधी मामलों एवं प्रमाण-पत्र से जुड़ी समस्याओं का निराकरण

ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन

समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध समाधान



जन-कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन



उद्देश्य

विकास कार्यों को मिलेगी गति



पारदर्शिता और जवाबदेही से 'जनकल्याण' होगा सुनिश्चित



संवाद से संपूर्ण समाधान



छत्तीसगढ़
सहस्र जयसंपर्क

Visit us : [f](https://www.facebook.com/ChhattisgarhCMO) [x](https://www.twitter.com/ChhattisgarhCMO) [y](https://www.youtube.com/ChhattisgarhCMO) [i](https://www.instagram.com/ChhattisgarhCMO) /ChhattisgarhCMO [f](https://www.facebook.com/DPRChhattisgarh) [x](https://www.twitter.com/DPRChhattisgarh) [y](https://www.youtube.com/DPRChhattisgarh) [i](https://www.instagram.com/DPRChhattisgarh) /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

RO. No. 13786/21

स्वतंत्र बोल

www.swatantrabol.com

वर्ष : 04, अंक : 12, मई 2026

प्रेरणास्रोत

स्व. जीवन गिरि गोस्वामी



संपादक

राहुल गिरि गोस्वामी



कानूनी सलाहकार

आनंद मोहन तिवारी

दिनेश मिश्रा



प्रचार-प्रसार-विज्ञापन

शेखर सागर



ले-आउट/डिजाइन

द्वारिका प्रसाद साहू

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक

राहुल गिरि गोस्वामी द्वारा

डी-317 बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने

टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)

पिन-492001 से प्रकाशित

एवं सागर प्रिंटर्स, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.)

पिन-492001 से मुद्रित।

सम्पादक - राहुल गिरि गोस्वामी

रजिस्टर्ड कार्यालय

डी-317 बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने

टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)

पिन-492001

Email : Bolswatantra@gmail.com

Phone : 9754374333

(समस्त न्यायालीन प्रकरणों के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र रायपुर होगा।)

विदेशी फंडिंग से हो रहा धर्मांतरण

03



प्रदेश भर में शुरू हुआ Dial 112 अमीत शाह... 05

सुशासन तिहार - शिविर में बना जन्म... 10

‘छिंद के बीजों से तैयार होगी कैफीन मुक्त हर्बल कॉफी’ 12

‘बस्तर का वेस्ट-अब बनेगा बेस्ट’

विष्णुदेव साय सौम्य व्यक्तित्व, सख्त प्रशासन.. 17



ईंधन कम जलाएं, ‘वर्क फ्रॉम होम’... 23

‘मुख्यमंत्री साय ने बरगद पेड़ के नीचे... 24

सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन की योजनाओं... 26



सुशासन तिहार में उमड़ रही भीड़ बता रही सब ठीक नहीं...

छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन तिहार मना रही है। इस तिहार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं और मांगों को सुन रहे.. इस तिहार में सरकार के योजनाओं की जमीनी हकीकत और प्रशासन की दक्षता और फेलियर दिख रही है। सुशासन तिहार के शिविरों में उमड़ने वाली भीड़ बता रही कि लोग छोटे छोटे कार्यों के लिए परेशान हैं , सरकारी विभागों में उनका काम नहीं हो रहा और जब भी मौका मिलता है तो काम होने की उम्मीद से भीड़ बढ़ जाती है। जिलों में कलेक्टर जनदर्शन होता है, राजधानी में स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनदर्शन करते हैं और मंत्रियों द्वारा भी समाधान शिविरों का आयोजन होने करने के बाद भी अगर लोगों की भीड़ उमड़ रही तो सरकार को सोचना होगा कि ऐसी स्थिति निर्मित क्यों रही? सरकार को ढाई साल पुरे हो गए ऐसे में गंभीरता से इस पर विचार करना होगा जिससे सुशासन सिर्फ नाम तक ना सिमटा रहे।

– राहुल गोस्वामी

विदेशी फंडिंग से हो रहा धर्मांतरण

लोगों को ईसाई बनाने के लिए 95 करोड़ का लेनदेन ईडी के प्रेसनोट में चौंकाने वाले तथ्य

छत्तीसगढ़ में कथित धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग और चर्च-प्लांटिंग नेटवर्क को लेकर जांच तेज हो गई है। कुछ दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में विदेशी डेबिट कार्ड्स के जरिए करोड़ों रुपए भारत लाने का खुलासा हुआ था। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मिशनरी संगठन द टिमोथी इनिशिएटिव (TTI) का नाम चर्चा में है।

द टिमोथी इनिशिएटिव (TTI) एक अंतरराष्ट्रीय ईसाई मिशनरी संगठन है, जो दुनिया के हर गांव में चर्च स्थापित करने के उद्देश्य से काम करने का दावा करता है। पुलिस, ईडी और अन्य एजेंसियां राज्य में एक्टिव लोकल पास्टर नेटवर्क, ट्रेनिंग मॉड्यूल और फंडिंग ट्रेल की जांच कर रही हैं।

बस्तर, धमतरी से राजनांदगांव तक अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों से कनेक्शन की जांच की जा रही है। एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या यहां इस्तेमाल किया गया मॉडल TTI के नेटवर्क जैसा है। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता तक सीमित नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है।

भाजपा सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि कांग्रेस इसलिए ED जांच से बचती थी। ग्रामीणों इलाकों में आदिवासियों के बीच गतिविधियां फॉरेन फंडिंग से चलती थी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये ट्रांजेक्शन भाजपा सरकार के समय हुए हैं।

द टिमोथी इनिशिएटिव संगठन के बारे में जानिए

द टिमोथी इनिशिएटिव (TTI) खुद को एक वैश्विक ईसाई मिशनरी संगठन बताता है, जिसका लक्ष्य 'हर गांव में चर्च' स्थापित करना है। संगठन के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मुताबिक 2007 से अब तक 50 देशों में 2.68 लाख से ज्यादा चर्च स्थापित किए जा चुके हैं। लाखों लोगों को 'डिसाइपल' यानी अनुयायी बनाने का दावा किया गया है।

भारत में इसके चर्चों और नेटवर्क की अलग से



आधिकारिक संख्या सार्वजनिक नहीं है, लेकिन विभिन्न पार्टनर संस्थाओं की रिपोर्ट में उत्तर भारत में 3,000 से ज्यादा हाउस चर्च और दक्षिण भारत में 7,000 से ज्यादा चर्चों की जानकारी मिलती है।

संगठन कैसे करता था ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार

टीटीआई का मॉडल बाइबल की आयत 2 टिमोथी 2:2 पर आधारित बताया जाता है। इसमें एक 'Paul' मास्टर ट्रेनर, कई 'Timothy' चर्च प्लांटर और 'Titus' शिष्य तैयार करता है। यह मल्टी-लेयर नेटवर्क गांव-गांव तक पहुंचकर छोटे 'हाउस चर्च' और प्रेरण गुप के जरिए विस्तार करता है।

जांच एजेंसियों का मानना है कि अगर बैंक खातों, विदेशी कार्ड एगिजट, सोशल मीडिया नेटवर्क, ट्रेनिंग मॉड्यूल और स्थानीय पास्टरों के संपर्कों का लिंक जुड़ता है तो बड़ा खुलासा हो सकता है। इस दिशा में एजेंसियां लगातार जांच कर रही है।

ED के एक्शन से छत्तीसगढ़ में एक्टिव होने का इनपुट मिला

छत्तीसगढ़ में इस नेटवर्क के एक्टिव होने के संकेत

तब मिले, जब ED की हालिया रिपोर्ट में नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच विदेशी डेबिट कार्ड्स के जरिए करीब 95 करोड़ रुपए भारत में लाए जाने का खुलासा हुआ।

जांच में सामने आया कि इसमें से करीब 6.5 करोड़ रुपए केवल बस्तर और धमतरी जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से निकाले गए। एजेंसियों को शक है कि इस रकम का इस्तेमाल चर्च-प्लांटिंग, लोकल नेटवर्किंग और धर्म प्रचार गतिविधियों में किया गया हो सकता है।

जिलों में धर्मांतरण-मतांतरण का केस ज्यादा

छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण-मतांतरण को लेकर विवाद जारी है। बीते दिनों बस्तर में पादरी की भी पिटाई हुई। बीते तीन साल से हर संडे ईसाई-हिंदू संगठन प्रेयर करने के विवाद पर भिड़ रहे हैं।

जशपुर, सरगुजा, रायगढ़, कबीरधाम, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोंडागांव और नारायणपुर में धर्मांतरण-मतांतरण के मुद्दों पर लगातार विवाद जैसे स्थिति हो रही है। इन इलाकों में आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे 'हाउस चर्च', प्रेयर ग्रुप और लोकल पास्टर नेटवर्क के जरिए प्रचार-प्रसार किए जाने की शिकायतें समय-समय पर आती रही हैं।

पुलिस ने धरमपुरा इलाके में की थी कार्रवाई

राजनांदगांव पुलिस ने कुछ महीने पहले धर्मांतरण मामले में पास्टर डेविड चाकों को अरेस्ट किया था। पुलिस को यहां कार्रवाई के दौरान नाबालिगों को आश्रय में रखने की जानकारी मिली थी। मौके से ट्रेनिंग मॉड्यूल, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।

डेविड पर लोगों को पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने और बिना अनुमति के आश्रम चलाने का आरोप है। हालांकि, इस केस में TTI का नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या यहां इस्तेमाल किया गया मॉडल TTI के नेटवर्क जैसा है।

सामाजिक समरसता के लिए चिंता की बात- जूदेव

बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि जिस प्रकार विदेशी फंडिंग के माध्यम से संगठित



गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। यह सामाजिक समरसता और परंपरागत मूल्यों के लिए चिंताजनक है। यह मुद्दा केवल विदेशी फंडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्मांतरण से भी जुड़ा हुआ है।

कांग्रेस पार्टी इसलिए ED जांच से बचती थी- पांडेय

BJP सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भूपेश बघेल ने ED पर प्रतिबंध लगाया था। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी मामले में जांच हो। सूरजुराम टेकाम से लेकर समेत कई नाम सामने आए हैं।

कांग्रेस पार्टी इसलिए ED जांच से बचती थी। ग्रामीणों इलाकों में आदिवासियों के बीच गतिविधियां फॉरेन फंडिंग से चलती थी। नक्सलियों के बीच कांग्रेसियों का नेटवर्क था, आने वाले समय में और खुलासा होगा।

बीजेपी के कार्यकाल में हुए ट्रांजेक्शन- कांग्रेस

वहीं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस मामले में 2024-25 में पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ है, इस समय भाजपा सरकार रही है। इसी दौरान धर्मांतरण के मामले भी बढ़ें। विदेशी नागरिकों की गतिविधियां बढ़ी। BJP बौखला कर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। सरकार को जवाब देना चाहिए।

‘नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112 सेवा’ और मोबाइल फॉरेंसिक वैन का किया शुभारंभ

प्रदेश भर में शुरू हुआ Dial 112 अमीत शाह ने किया रवाना...



केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने माना पुलिस परेड ग्राउंड, रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस की अत्याधुनिक ‘नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112 सेवा’ तथा मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष श्री रमन सिंह एवं की गरिमामयी उपस्थिति में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने 400 अत्याधुनिक डायल-112 वाहनों तथा 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि ‘एक्के नंबर, सब्बो बर’ थीम पर आधारित यह आधुनिक सेवा पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा सेवाओं को एकीकृत करते हुए नागरिकों को एक ही नंबर पर त्वरित आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराएगी। इसके तहत शुरू किए गए 400 अत्याधुनिक वाहनों में स्मार्टफोन, जीपीएस, वायरलेस रेडियो, पीटीजेड कैमरा, डैश कैम, मोबाइल एनवीआर और सोलर बैकअप जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इन तकनीकों की मदद से घटनास्थल की लाइव मॉनिटरिंग, रियल-टाइम ट्रैकिंग और त्वरित संचार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

यह सेवा 24x7 संचालित होगी। इसमें जीआईएस आधारित मॉनिटरिंग, एडवांस व्हीकल ट्रैकिंग, एसआईपी ट्रंक टेक्नोलॉजी तथा स्वचालित कॉलर लोकेशन पहचान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। राज्य के सभी 33 जिला समन्वय केंद्रों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा गया है। नागरिक वॉयस कॉल, एसएमएस, ईमेल, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, चैटबॉट और SOS-112 इंडिया ऐप के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।



मोबाइल फॉरेंसिक वैन से घटनास्थल पर ही होगी वैज्ञानिक जांच

‘Science on Wheels - Towards Faster Justice’ थीम पर आधारित 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन प्रदेश में अपराध अनुसंधान को नई दिशा देंगी। ‘32 वैन - 32 जिले - एक संकल्प: सटीक जांच, त्वरित न्याय’ के उद्देश्य के साथ शुरू की गई यह पहल घटनास्थल पर ही प्रारंभिक वैज्ञानिक जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगी।

लगभग 65 लाख रुपये प्रति यूनिट लागत वाली इन अत्याधुनिक वैन में घटनास्थल संरक्षण किट, साक्ष्य

संग्रहण एवं सीलिंग उपकरण, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन सिस्टम, नार्कोटिक्स परीक्षण किट, डिजिटल फॉरेंसिक सपोर्ट, उच्च गुणवत्ता फोटोग्राफी व्यवस्था, बुलेट होल स्क्रीनिंग एवं बैलिस्टिक जांच किट तथा गनशॉट रेजिड्यू (तस्क्रे) परीक्षण किट जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अब तक अपराध स्थल से साक्ष्य प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने में समय लगता था, जिससे साक्ष्यों के दूषित होने की संभावना बनी रहती थी तथा रिपोर्ट आने में भी विलंब होता था। नई मोबाइल फॉरेंसिक वैन के माध्यम से घटनास्थल पर ही प्रारंभिक जांच, साक्ष्य संरक्षण, परीक्षण और डिजिटल दस्तावेजीकरण किया जा सकेगा। इससे जांच की गुणवत्ता और गति दोनों में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

साक्ष्य आधारित न्याय व्यवस्था को मिलेगा नया बल

राज्य सरकार का उद्देश्य वैज्ञानिक जांच को जन-जन तक पहुंचाना, साक्ष्य आधारित न्याय प्रणाली को मजबूत करना, अपराध नियंत्रण में फॉरेंसिक विज्ञान की भूमिका को बढ़ाना तथा समयबद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित करना है।

आधुनिक डायल-112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन के संचालन से प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा, अपराध अनुसंधान को नई गति मिलेगी तथा आम नागरिकों का कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।



सुशासन तिहार

पेड़ की छांव के नीचे चौपाल, अपनों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री...



प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत मुंगेली जिला विकास, जनकल्याण और सुशासन के एक ऐतिहासिक अध्याय का साक्षी बना। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जिला मुख्यालय स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल होकर जिले को 353 करोड़ 58 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले 414 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 152 करोड़ 02 लाख रुपये से अधिक की लागत के 284 कार्यों का लोकार्पण तथा 201 करोड़ 56 लाख रुपये से अधिक की लागत के 130 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इन कार्यों से जिले में आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और जनसुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम में केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम तथा जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक, मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले, तखतपुर विधायक धरमजीत सिंह, बेलतरा

विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय, नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम के दौरान पुष्प वाटिका एवं चौपाटी, नहर, एनीकट, लाइवलीहुड

कॉलेज भवन पहुंच मार्ग, मुंगेली-भटगांव पहुंच मार्ग सहित अनेक सड़क निर्माण कार्यों, महतारी सदनो, छात्रावासों, जल जीवन मिशन के कार्यों, सामुदायिक भवनों, अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों, प्राथमिक शाला भवनों, सांस्कृतिक मंचों, सीसी सड़कों, अमृत सरोवरों तथा आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही विभिन्न ग्रामों में सीसी सड़क, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सड़क मार्ग, एसटीपी निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण, फुटपाथ और पुल निर्माण सहित अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद विद्यालय मोतिमपुर, लालपुरथाना, लोरमी, पथरिया और सरगांव का वर्चुअल लोकार्पण भी किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन सरकार विकास और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुंगेली जिले को मिली विकास कार्यों की यह बड़ी सौगात आने वाले समय में जिले के विकास को नई गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से आमजनों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है तथा शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर भक्ति और श्रम की प्रतीक माता कर्मा, सामाजिक समरसता के प्रतीक बाबा गुरु घासीदास, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर तथा शौर्य और त्याग के प्रतीक महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का अनावरण करते हुए कहा कि ये महापुरुष समाज को प्रेरणा देने वाले आदर्श हैं। उन्होंने नवागढ़ रोड में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापना के लिए 25 लाख रुपये, मुंगेली में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास भवन निर्माण, मेला नवागांव में बाउंड्रीवाल एवं प्रवेश द्वार निर्माण के लिए 20 लाख रुपये तथा सीसी सड़क निर्माण के लिए 10 लाख रुपये

की घोषणा की। साथ ही चिकित्सा महाविद्यालय की मांग को पूरा करने के लिए सकारात्मक आश्वासन दिया।

केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने जिले को मिली 353 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात के लिए मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास और सुशासन को नई दिशा मिल रही है।

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार जनता के दुख-दर्द को समझते हुए त्वरित निर्णय ले रही है और मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि मुंगेली जिला निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और यह सब मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। विधायक पुनूलाल मोहले ने जिले में हो रहे विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री एवं सहायता राशि वितरित कर लाभान्वित भी किया। उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिले के चार विद्यार्थियों अंशुल शर्मा, नंदिता देवांगन, हेमा साहू और चैतूराम साहू को लैपटॉप प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास की चाबियां, मनियारी बैराज योजना से प्रभावित परिवारों को प्रतिकात्मक चेक, मछुआरों को मछली जाल एवं आइस बॉक्स, किसानों को मिनी किट तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता सामग्री वितरित की। कुल 282 से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

कार्यक्रम के अंत में जिला प्रशासन द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संभागायुक्त सुनील जैन, आईजी बिलासपुर रामगोपाल गर्ग, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, डीएफओ अभिनव कुमार, अतिरिक्त कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

जनकल्याणकारी योजनाओं से मजबूत हुआ रोजगार का आधार

भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) 2025 के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम होकर 2.3 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह आंकड़ा प्रदेश की मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगारोन्मुखी नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

राज्य सरकार की प्राथमिकता केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि लोगों को सम्मानजनक आजीविका, स्थायी आय और आत्मनिर्भरता से जोड़ना रही है। यही कारण है कि खेती, वनोपज, स्वरोजगार और लघु उद्यमों पर आधारित आर्थिक गतिविधियों ने प्रदेश में रोजगार के अवसरों को लगातार मजबूत किया है।

प्रदेश में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को आर्थिक विकास की धुरी बनाते हुए किसानों, ग्रामीणों और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया गया है। समर्थन मूल्य पर वनोपज खरीदी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विस्तार, कौशल विकास कार्यक्रमों तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की योजनाओं ने युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांवों में आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ा है, जिससे पलायन में कमी आने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

राज्य सरकार का मानना है कि केवल बेरोजगारी के आंकड़े कम होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं को उनकी क्षमता और कौशल के अनुरूप बेहतर अवसर उपलब्ध कराना अधिक महत्वपूर्ण है। इसी सोच के अनुरूप कौशल उन्नयन, उद्यमिता विकास,



रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और निवेश आधारित औद्योगिक विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नई औद्योगिक नीति के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं, जहां प्रदेश में लगातार नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। सरकार ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करते हुए विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प छत्तीसगढ़ के प्रत्येक युवा, किसान, महिला और श्रमिक को आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास और रोजगार के नए अवसरों का निरंतर विस्तार किया जा रहा है, ताकि आर्थिक प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनहितकारी योजनाओं, सुशासन और रोजगारोन्मुखी नीतियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के अग्रणी विकासशील राज्यों में अपनी मजबूत पहचान और अधिक सुदृढ़ करेगा।

सुशासन तिहार - शिविर में बना जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड...

शिविर में ही बना जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, वर्षों की परेशानी हुई दूर



शासन की महत्वाकांक्षी पहल सुशासन तिहार अब जरूरतमंद लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही है। बस्तर जिले के दरभा विकासखंड के ग्राम ढोढ़ेपाल में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में एक ऐसा ही भावुक और प्रेरणादायक मामला सामने आया, जहां मोटली सोढ़ी को जीवन में पहली बार सरकारी दस्तावेज प्राप्त हुए।

ग्राम छोटे गुडरा डिलमिली निवासी मोटली सोढ़ी (पति श्री बोंजा सोढ़ी) के पास अब तक कोई भी पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं था। दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सुशासन तिहार शिविर में जब अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली, तब तत्काल पहल करते हुए पंचनामा तैयार कराया गया और मौके पर ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी

कर मोटली सोढ़ी का जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया। साथ ही आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी शिविर में ही पूरी की गई।

सरकारी दस्तावेज मिलने के बाद मोटली सोढ़ी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। उन्होंने कहा कि अब उन्हें भी शासन की योजनाओं का लाभ मिलने की उम्मीद जगी है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन की इस संवेदनशील पहल की सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि सुशासन तिहार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। शिविर में लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जा रहा है, जिससे आमजन को राहत मिल रही है। सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन न केवल समस्याओं का समाधान कर रहा है, बल्कि जरूरतमंद लोगों के जीवन में नई आशा और विश्वास भी जगा रहा है।



बेटियों की राह आसान हो रहा...

छत्तीसगढ़ की बेटियां अब न केवल स्कूल जा रही हैं, बल्कि उच्च शिक्षा की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। राज्य में 'सरस्वती साइकिल योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन से उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्राओं के नामांकन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ अब इस मामले में 73.6 प्रतिशत के आंकड़े के साथ राष्ट्रीय औसत (58.2 प्रतिशत) को काफी पीछे छोड़ चुका है।

सरस्वती साइकिल योजना

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। राज्य सरकार का मानना है कि इस सफलता के पीछे सबसे बड़ी भूमिका सरस्वती साइकिल योजना की है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने 1.5 लाख साइकिलों के वितरण का जो लक्ष्य रखा था, वह अब पूर्णता की ओर है।

ड्रॉप-आउट पर लगाम

कक्षा 9वीं में प्रवेश लेते ही मुफ्त साइकिल मिलने से माध्यमिक स्तर के बाद स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं की संख्या में भारी कमी आई है। दूरी की बाधा हुई खत्म, बढ़ा आत्मविश्वास विशेषज्ञों और शिक्षा विभाग के अनुसार, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल की दूरी बालिकाओं की शिक्षा में सबसे बड़ी रुकावट थी। साइकिल ने इस भौगोलिक बाधा को खत्म कर दिया है।

सुगम आवागमन

अब दूरदराज के गांवों की छात्राएं भी कई किलोमीटर दूर स्थित उच्च माध्यमिक स्कूलों तक आसानी से पहुंच रही हैं। साइकिल न केवल समय बचा रही है, बल्कि छात्राओं के स्कूल अटेंडेंस और आत्मविश्वास में भी उल्लेखनीय सुधार ला रही है।

एक दशक का सफर

आंकड़ों की जुबानी छत्तीसगढ़ में उच्च माध्यमिक



शिक्षा के प्रति बढ़ता रुझान इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है विवरण वर्ष 2010-11 वर्तमान स्थिति (2026) छात्राओं की सकल नामांकन 33.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021-22 68.1 प्रतिशत रहा। छत्तीसगढ़ अब इस मामले में 73.6 प्रतिशत के आंकड़े के साथ राष्ट्रीय औसत 58.2 प्रतिशत को काफी पीछे छोड़ चुका है। उल्लेखनीय है कि इस योजना की शुरुआत वर्ष 2004-05 में तत्कालीन सरकार द्वारा की गई थी। बीच के कुछ वर्षों में इस योजना के बंद होने के बावजूद दिसंबर 2023 में साय सरकार के आते ही इसे पुनः प्रभावी ढंग से लागू किया गया, जिससे स्कूली बालिकाओं के स्कूल में नियमित उपस्थिति में वृद्धि हुई।

बेटियों के सपनों को मिली गति

मुख्यमंत्री का संकल्प हमारी प्राथमिकता है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां, विशेषकर आदिवासी अंचलों की छात्राएं, शिक्षा के क्षेत्र में देश के किसी भी अन्य राज्य से पीछे न रहें। सरस्वती साइकिल योजना केवल एक वितरण कार्यक्रम नहीं, बल्कि बेटियों के सपनों को गति देने का माध्यम है।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह योजना एक वरदान साबित हुई है। छत्तीसगढ़ की यह उपलब्धि दर्शाती है कि सही नीति और संवेदनशील नेतृत्व से सामाजिक बदलाव की नींव कितनी मजबूत रखी जा सकती है।

‘छिंद के बीजों से तैयार होगी कैफीन मुक्त हर्बल कॉफी’

‘बस्तर का वेस्ट-अब बनेगा बेस्ट’



बस्तर के नैसर्गिक सौंदर्य और समृद्ध संसाधनों के बीच अब एक नई और सुगंधित क्रांति आकार ले रही है, जिसका श्रेय दंतेवाड़ा जिले के बचेली निवासी युवा उद्यमी विशाल हालदार को जाता है। बीकॉम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की शिक्षा प्राप्त करने वाले विशाल ने अपनी जड़ों से जुड़े रहने और कुछ नया करने की चाह में छिंद (खजूर की एक स्थानीय प्रजाति) के उन बीजों से हर्बल कॉफी तैयार की है, जिन्हें अब तक बस्तर में पूरी तरह व्यर्थ समझा जाता था। इस अभिनव प्रयोग के पीछे विशाल का उद्देश्य न केवल बेकार पड़े प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना है, बल्कि कॉफी के उन शौकीनों को एक स्वस्थ विकल्प प्रदान करना है जो स्वाद तो चाहते हैं लेकिन कैफीन के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं। विशाल का यह सफर करीब दो वर्षों के गहन शोध और प्रयोगों का परिणाम है, जिसमें उन्होंने इंटरनेट की मदद और स्थानीय समझ का बखूबी तालमेल बिठाया है। विशाल की इस नवाचार को इनोवेशन महाकुंभ में प्रथम स्थान मिला, जिसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा सम्मानित किया गया।

इस हर्बल कॉफी की सबसे प्रभावशाली विशेषता इसका पूरी तरह से कैफीन मुक्त होना है, जबकि इसमें छिंद के प्राकृतिक गुणों के कारण प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। विशाल का मानना है कि अधिकांश लोग केवल मानसिक सक्रियता के लिए ही

नहीं, बल्कि कॉफी के अनूठे स्वाद और उसकी आदत के कारण इसका सेवन करते हैं, और उनकी यह खोज इसी वर्ग को ध्यान में रखकर की गई है। इस नवाचार को तब बड़ी पहचान मिली जब विशाल ने शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर में आयोजित इनोवेशन महाकुंभ में अपना स्टॉल लगाया। वहाँ प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और आम जनता ने इस कॉफी का स्वाद चखा और इसकी खूब सराहना की। विशाल केवल एक उत्पाद बनाने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के यूथ अप फाउंडेशन के माध्यम से स्थानीय युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके इस आइडिया से बस्तर के ग्रामीणों को रोजगार मिले और गांवों और जंगल से मिलने वाले छिंद के बीजों से उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। हालांकि यह प्रोजेक्ट अभी भी टेस्टिंग और विकास के दौर में है और इसका आधिकारिक लॉन्च होना बाकी है, लेकिन विशाल के इस अटूट प्रयास ने यह साबित कर दिया है कि यदि दृष्टि स्पष्ट हो तो स्थानीय वेस्ट को भी वैश्विक स्तर के बेस्ट उत्पाद में बदला जा सकता है। आने वाले समय में यह हर्बल कॉफी न केवल बस्तर की पहचान बन सकती है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक दुनिया के लिए एक अनूठा उपहार भी साबित हो सकती है।

तेंदूपत्ता खरीदी की बढ़ी दर ने संग्राहकों का बढ़ाया उत्साह व भरोसा, हर फड़ पर रौनक 'हरा सोना' बना समृद्धि का आधार

जेठ की तपती धूप के बीच रामपुर के जंगलों में एक बार फिर 'हरे सोने' यानी तेंदूपत्ता संग्रहण की रौनक लौट आई है। लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए इस सीजन ने ग्रामीणों, खासकर महिलाओं के चेहरों पर नई उम्मीदों की मुस्कान ला दी है। इस वर्ष संग्रहण कार्य की विधिवत शुरुआत रामपुर केंद्र में पूजा-अर्चना के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिला हितग्राही शामिल हुए।

सुबह सूरज उगने से पहले ही कोरबा जिले के रामपुर की कारी बाई पटेल और खेमबाई पटेल अपने परिवारों के साथ जंगल पहुँच गई थीं। दोपहर होते-होते जब वे तेंदूपत्ते की गड़ियाँ लेकर खरीदी केंद्र पहुँचीं, तो वहाँ का माहौल उत्सव जैसा दिखाई दिया। कई तेंदूपत्ता संग्राहकों के बीच दोनों ने खरीदी केंद्र में 'बोहनी' की।

कारी बाई ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी खरीदी समय पर शुरू होने से उन्हें बिचौलियों से राहत मिली है। सीधे फड़ में पत्ता बेचने से उचित पारिश्रमिक और बोनस की गारंटी मिलती है, जिससे पूरे साल का आर्थिक प्रबंधन सुगमता से चलता है।

शासन द्वारा इस वर्ष तेंदूपत्ता खरीदी की दर बढ़ाकर 4 हजार रुपये से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा करने का सकारात्मक असर ग्रामीण परिवारों की आय पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बढ़े हुए दर से संग्राहकों का उत्साह व भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है। रामपुर क्षेत्र में तेंदूपत्ता सीजन जनजातीय परिवारों के लिए आजीविका का मुख्य आधार है। सावधानी से पत्ता तोड़ना, छंटाई करना और गड़ियाँ तैयार करना एक कठिन परंतु महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से अहम है।

वनोपज समिति प्रबंधकों के अनुसार इस वर्ष खरीदी व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित



बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। फड़ में गड़ियों की गिनती और गुणवत्ता परीक्षण आधुनिक मापदंडों के आधार पर किया जा रहा है। संग्राहकों के बैंक खातों में पारिश्रमिक का भुगतान डिजिटल माध्यम से तुरंत सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे किसी प्रकार की देरी या असुविधा न हो।

अनुकूल मौसम के कारण इस बार पत्तों की गुणवत्ता बेहतर है, जिससे संग्राहकों की आय बढ़ने की संभावना और मजबूत हो गई है। ग्रामीणों के लिए 'हरा सोना' केवल एक वनोपज नहीं बल्कि उनके स्वावलंबन और आर्थिक स्थिरता का आधार बन गया है।

प्रशासन ने सभी संग्राहकों से अपील की है कि वे शासन द्वारा निर्धारित दरों और मानकों का पालन करते हुए अपना तेंदूपत्ता केवल सहकारी समिति केंद्रों पर ही बेचें, जिससे उन्हें योजनाओं व बोनस का पूरा और सीधा लाभ मिल सके। रामपुर की मेहनतकश महिलाओं की लगन, जंगलों की हरियाली और शासन की दूरदर्शी पहल... इन तीनों ने मिलकर 'हरे सोने' को ग्रामीण समृद्धि का सशक्त माध्यम बना दिया है।

कबाड़ से कला तक

वेस्ट टू बेस्ट इको पार्क बना छत्तीसगढ़ के लिए आकर्षण का केंद्र



छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले ने स्वच्छता और सृजनात्मकता की एक नई इबारत लिखी है। दुलदुला जनपद पंचायत के पास विकसित किया गया इको पार्क आज न केवल आकर्षण का केंद्र है, बल्कि वेस्ट टू बेस्ट (कबाड़ से जुगाड़) की अवधारणा को सार्थक करने वाला एक सफल मॉडल बनकर उभरा है। अनुपयोगी कचरे को सौंदर्य में बदलकर इस पार्क ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज की सोच को नई दिशा दी है।

इस पार्क की सबसे बड़ी शक्ति इसकी निर्माण शैली है। यहाँ उन वस्तुओं को जीवन दिया गया है जिन्हें लोग अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं। लोहे का कमाल पुराने लोहे के कबाड़ और मशीनरी पार्ट्स का उपयोग कर घोड़ा, मयूर और तितली जैसी सजीव व आकर्षक कलाकृतियाँ गढ़ी गई हैं। पुराने और घिसे हुए टायरों को चटकीले रंगों से सजाकर झूलों में तब्दील किया गया है, जो बच्चों के लिए खुशी का ठिकाना बन गए हैं।

सुविधाएं, सेहत और मनोरंजन का वन-स्टॉप डेस्टिनेशन

इको पार्क को एक बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र के रूप में ढाला गया है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक युवाओं और बुजुर्गों के लिए आधुनिक ओपन जिम की स्थापना की गई है। बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित और रचनात्मक खेल सामग्रियों का प्रबंधन किया गया है।



शाम के समय सुकून बिताने के लिए यह स्थान परिवारों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन चुका है।

प्रशासनिक पहल- हरियाली और विस्तार पर जोर

हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान इस नवाचार की मुक्तकंठ से सराहना की गई। पार्क की निरंतरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं परिसर को अधिक हरा-भरा बनाने के लिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। नियमित रखरखाव के लिए स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए समर्पित टीम की व्यवस्था की गई है। जन- सुविधाओं का विस्तार कर इसे एक राज्य स्तरीय मॉडल के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। दुलदुला का यह इको पार्क संदेश देता है कि सीमित संसाधनों और रचनात्मक सोच के साथ हम पर्यावरण संरक्षण और जन-कल्याण का शानदार समन्वय कर सकते हैं।

भविष्य की राह

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पार्क छत्तीसगढ़ के अन्य विकासखंडों के लिए शपथ-प्रदर्शक का कार्य करेगा। यह मॉडल न केवल कचरा प्रबंधन (Waste

Management) की समस्या का समाधान करता है, बल्कि कम लागत में पर्यटन और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम भी है। जशपुर का यह प्रयोग साबित करता है कि यदि इच्छाशक्ति हो, तो कबाड़ भी सोना बन सकता है।



विष्णुदेव साय सौम्य व्यक्तित्व, सख्त प्रशासन..



स्वतंत्र बोल टीम

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी सादगी और सरलता के जाने जाते हैं। राजनीति में सरल होना आसान नहीं है, पर विष्णुदेव साय ने इस मिथक को भी तोड़ दिया है। उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि सरलता और सादगी के साथ भी प्रशासन चलाया जा सकता है। प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है, प्रदेश के मुखियां स्वयं भीषण गर्मी में लोगो के बीच जाकर, चौपाल लगाकर मिल रहे और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय सादगी के सख्ती के चर्चा में बने हुए हैं। मुख्यमंत्री साय को जमीन से जुड़े नेता के रूप में देखा जा रहा है, जो आम जनता से सीधे जुड़कर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समय पर समाधान

के निर्देश देते हैं। प्रशासनिक बैठकों में वे साफ-सुथरी और सख्त कार्यप्रणाली पर जोर देते हैं और लापरवाही को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी भी देते हैं। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए वे लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। जनता से जुड़े मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश देकर उन्होंने अपनी सख्त छवि को मजबूत किया है, जबकि आम लोगों के बीच उनकी सरल और सहज व्यवहार शैली की भी सराहना हो रही है। सीएम साय की यह

कार्यशैली प्रशासनिक सुधार और जनता के भरोसे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सहायक आयुक्त को सस्पेंड किया-

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वाभाव सरल है पर प्रशासन में गड़बड़ी करने वालो तत्काल कड़ी कार्यवाही करने में संकोच नहीं करते। सुशासन तिहार में सरगुजा संभाग के सूरजपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी जिले के औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शिविर में वह ग्रामीणों आत्मीयता से मिले एवं धैर्य से उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री ने चिरमिरी में जिलों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में तीनों जिलों के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या और स्कूली



परीक्षा परिणाम की स्थिति को लेकर गहरी नाराजगी जताया, तो कोरिया जिले में किसानों को खाद वितरण में गड़बड़ी करने वाले सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं आयुष प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सख्त रुख से सभी लोग सकते में आ गए। वहीं दूसरी ओर शासकीय कामकाज में लापरवाही के मामले में अधिकारियों पर नाराजगी और निलंबन की कार्यवाही सख्त प्रशासनिक व्यवस्था का स्पष्ट संकेत दिया।

अशिष्ट व्यवहार बर्दाश्त नहीं-

मुख्यमंत्री साय जीतने सरल है उतना ही प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखने कठोरता दिखाने देरी नहीं करते। सुशासन तिहार में दुर्ग जिले के जनसमस्या निवारण शिविर में आम जनता से अशिष्ट व्यवहार और कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर जनपद पंचायत के सीईओ को सस्पेंड कर साय ने कार्यकर्ताओं को मेसेज दिया। सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो से अच्छा मैसेज नहीं गया, लोगो की बढ़ती नाराजगी के त्वरित निर्णय लेते हुए के प्रति जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

अखबार में प्रकाशित पेयजल समस्या की खबर पर लिया त्वरित संज्ञान सरगुजा जिले के मैनापाट क्षेत्र की चराजोबला बस्ती में पेयजल समस्या से संबंधित समाचार पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री साय सुबह अखबार पढ़ते समय 'नाला और ढोढ़ी के दूषित जल पर आज भी निर्भर हैं वनवासी' शीर्षक से प्रकाशित खबर को गंभीरता से लिया और सरगुजा कलेक्टर को फोन कर प्रभावित बस्ती में शीघ्र पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चराजोबला बस्ती में पेयजल संकट की स्थिति का तत्काल स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार हैंडपंप खनन, वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था और दीर्घकालिक समाधान की दिशा

में प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जाए। जब मुख्यमंत्री साय ने थामा हाथ, तो दिव्यांग हितग्राही की जिंदगी में लौटी उम्मीद की रौशनी जिंदगी कभी-कभी इंसान की परीक्षा इतनी कठिन लेती है कि हर दिन एक संघर्ष बन जाता है।

सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र परिवार तक पहुंचे ष्टरुसाय का निर्देश -

बस्तर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे शासन का वास्तविक लाभ, शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो सुनिश्चित, शासन-प्रशासन की वास्तविक सफलता तभी है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और आम नागरिक को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े। सुशासन तिहार में जनता से आत्मीय बातचीत ष्टरु साय शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों से आत्मीय संवाद कर उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को करीब से जाना। मुख्यमंत्री ने महिलाओं, किसानों और ग्रामीण परिवारों से योजनाओं के लाभ, आयवृद्धि, आजीविका और जीवनस्तर में आए सुधारों की जानकारी लेते हुए कहा कि जब शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी सुशासन की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हितग्राहियों के अनुभव सुनने के बाद प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि योजनाओं का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देता है जब उसका लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचकर उसके जीवन में बदलाव लाए। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे शासन की योजनाओं की जानकारी लेकर उनका अधिकाधिक लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर, समृद्ध तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनें।

दरअसल राज्य के रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उनके हितों की रक्षा और उनके भोजन की व्यवस्था सरकार करे, और यह काम मुख्यमंत्री विष्णुदेव बखूबी कर रहे हैं। मौजूदा समय में प्रदेश का प्रतीक व्यक्ति आश्वतथ है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रहते उनके हितों के अनदेखी नहीं होगी। जीतनी सरलता से वे काम करते हैं उतनी ही तत्परता से निर्णय भी लेते हैं, और यही है विष्णु का सुशासन।

देश की सबसे लंबी कोटमसर गुफा

नैसर्गिक सुंदरता से भरपूर बस्तर की कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर देश की सबसे लंबी गुफा मौजूद है। पहले इस गुफा का नाम गोपनसर (छिपी हुई गुफा) गुफा था जिसे बाद में कोटमसर गांव के पास होने के कारण कोटमसर गुफा के नाम से पहचान मिली।

कोटमसर गुफा में क्या है खास

जगदलपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर स्थित कोटमसर गुफा को छत्तीसगढ़ का पाताल लोक भी कहा जाता है। इस गुफा में किसी भी तरफ से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। टॉर्च या गाइड की मदद से ही इस गुफा के अंदर पहुंचा जा सकता है। इस गुफा की खोज साल 1951 में प्रसिद्ध भूगोल वैज्ञानिक डॉ. शंकर तिवारी ने की थी। गुफा का निर्माण प्राकृतिक परिवर्तन के कारण पानी के प्रवाह के कारण हुआ है। चूने के पत्थर से बनी इस गुफा की बाहरी और आंतरिक सतह के अध्ययन से पता चलता है कि इसका निर्माण लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। कोटमसर गुफा 60 से लेकर 120 फीट गहरी है। 4500 फीट लंबी है। बस्तर के इस गुफा की तुलना विश्व की सबसे लंबी गुफा कर्लसवार ऑफ केव अमेरिका से की जाती है। जैव विविधताओं से भरे कांगेर वैली नेशनल पार्क में मौजूद कोटमसर गुफा भारत देश की सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है।

कोटमसर गुफा में मिलती है दुर्लभ मछलियां

कोटमसर गुफा के अंदर दुर्लभ प्रजाति की अंधी मछलियां पाई जाती है। ये मछलियां यहां बरसाती नाले में बाढ़ के दौरान कांगेर नदी से चढ़कर गुफा के कुंडों तक पहुंचती हैं। इन मछलियों को ग्रामीण पखना तुरु कहते हैं। जिसका वैज्ञानिक नाम इंडोनियोरेक्टस इवेजार्डी है। गुफा में अंधेरा होने के कारण इन मछलियों की आंखों की उपयोगिता खत्म होती गई जिससे उस पर चर्बी की परत चढ़ गई और वे अंधी हो गई। सूर्य की रोशनी नहीं मिलने के कारण मछलियों की त्वचा भी सफेद हो गई है। इसलिए इन्हें एल्बिनिक भी कहा जाता



है। इन मछलियों की 15 से 25 मिलीमीटर लंबी मूछें होती हैं। गुफा के पानी में मौजूद सूक्ष्म जीव इनका आहार है। गुफा में जमीन से लगभग 40 फीट की गहराई में महल के सभागार सा विशाल स्थान है। करीब 150 फीट तक ऊंची दीवारें और इसके ऊपर झूमरनुमा आकृतियां हैं।

देश की सबसे लंबी गुफा

बारिश में बंद रहती है कोटमसर गुफा: बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर मौजूद कोटमसर गुफा को बारिश के मौसम में पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है। गहरा होने के कारण बारिश के दिनों में बाढ़ का पानी गुफा के अंदर भर जाता है। इस दौरान गुफा के अंदर जाना काफी खतरनाक हो सकता है। इस वजह से बारिश के दिनों में कोटमसर गुफा बंद कर दी जाती है। शुक्रवार को कोटमसर गुफा पर्यटकों के लिए खोल दी गई हैं। कांगेर वैली प्रबंधक ने इस बार बस्तर आने वाले पर्यटकों के लिए खास इंतजाम किए हैं। यहां के स्थानीय लोगों के माध्यम से बस्तर की लोक संस्कृति रहन-सहन वेशभूषा रीति रिवाज और रहवास से पर्यटकों को रूबरू कराया जाएगा। नए नए पर्यटक स्थल व बस्तर की लोक सांस्कृतिक गतिविधियों को भी स्थापित किया है।

छत्तीसगढ़ जहां हर परंपरा में बसती है संस्कृति की आत्मा

मिट्टी की सौंधी महक



आत्मीयता और सामाजिक समरसता से परिपूर्ण है। यह प्रदेश विविधताओं से भरा हुआ ऐसा सांस्कृतिक क्षेत्र है, जहां आधुनिकता के बढ़ते प्रभाव के बावजूद लोकपरंपराएं आज भी लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी हुई हैं। गांवों की चौपालों से लेकर जनजातीय अंचलों तक यहां की संस्कृति हर पल जीवंत दिखाई देती है।

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली रही है। प्राचीन काल

आज आधुनिकता और वैश्वीकरण के दौर में भी छत्तीसगढ़ अपनी लोक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजकर आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार, सांस्कृतिक संस्थाएं और स्थानीय समुदाय लोककला, लोकनृत्य और जनजातीय परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पर्यटन और सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से प्रदेश की कला और संस्कृति को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल रही है।

छत्तीसगढ़ की संस्कृति केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान समाज की जीवंत चेतना है। यहां की लोक परंपराएं लोगों को प्रकृति से जुड़ना, सामूहिक जीवन जीना और अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाती हैं। लोकगीतों की मधुर धुन, मांदर की गूंज, त्योहारों की जीवंतता और लोगों की सहज आत्मीयता मिलकर छत्तीसगढ़ को भारतीय संस्कृति की एक अद्वितीय और गौरवशाली पहचान प्रदान करती है।

छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, पारंपरिक कला और जीवंत लोकजीवन के लिए पूरे देश में विशेष पहचान रखता है। यहां की संस्कृति मिट्टी की सौंधी खुशबू, लोकगीतों की मधुरता, जनजातीय परंपराओं की

में यह क्षेत्र दक्षिण कोसल के नाम से प्रसिद्ध था। रामायण काल से जुड़े अनेक प्रसंग यहां की धरती से संबंधित माने जाते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार भगवान श्रीराम ने अपने वनवास का लंबा समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। यही कारण है कि यहां की लोक आस्था, धार्मिक परंपराओं और लोकगीतों में रामकथा का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। समय के साथ यहां आदिवासी संस्कृति, ग्रामीण जीवन और विभिन्न समुदायों की परंपराओं ने मिलकर एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान का निर्माण किया है।

छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का सबसे सशक्त पक्ष यहां की लोकभाषा और लोकगीत हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा की मिठास और सहजता लोगों के व्यवहार में स्पष्ट रूप से झलकती है। यहां बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि भावनाओं और लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। इसके अलावा सरगुजिहा, हल्बी, गोंडी, कुडुख और अन्य जनजातीय बोलियां भी प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाती हैं। ग्रामीण परिवेश में आज भी ददरिया, सुआ गीत, करमा गीत और पंथी गीतों की गूंज सुनाई देती है। इन गीतों में

प्रेम, प्रकृति, श्रम, सामाजिक संबंध और लोक आस्था का सुंदर चित्रण मिलता है।

प्रदेश के लोकनृत्य यहां की सांस्कृतिक पहचान को विशेष रूप से दर्शाते हैं। लोकनृत्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि सामूहिक जीवन, सामाजिक उत्सव और धार्मिक आस्था का प्रतीक भी है। पंथी नृत्य सतनामी समाज की धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिसमें संत गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं और आध्यात्मिक भावनाओं का प्रभाव दिखाई देता है। राउत नाचा दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध लोकनृत्य है। इसी प्रकार करमा नृत्य आदिवासी समाज में प्रकृति और फसल उत्सव से जुड़ा हुआ है। मांदर और ढोल की थाप पर सामूहिक रूप से किया जाने वाला यह नृत्य जनजातीय जीवन की ऊर्जा और उत्साह को अभिव्यक्त करता है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सुआ नृत्य भी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बस्तर अंचल की जनजातीय संस्कृति छत्तीसगढ़ की आत्मा मानी जाती है। यहां रहने वाले गोंड, मुरिया, हल्बा, भतरा, माड़िया, भतरा और अन्य जनजातीय समुदाय आज भी अपनी पारंपरिक जीवनशैली, वेशभूषा और सांस्कृतिक मूल्यों को संजोए हुए हैं। जनजातीय समाज प्रकृति को जीवन का आधार मानता है। जंगल, नदी, पहाड़ और भूमि यहां केवल संसाधन नहीं, बल्कि आस्था और जीवन के प्रतीक हैं। बस्तर के हाट-बाजार केवल व्यापारिक केंद्र नहीं होते, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल के जीवंत मंच भी होते हैं। यहां लोकगीत, नृत्य, पारंपरिक वाद्ययंत्र और हस्तशिल्प एक साथ दिखाई देते हैं।

छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प भी देशभर में विशेष पहचान रखते हैं। बस्तर की ढोकरा कला विश्व प्रसिद्ध है। धातु से बनी पारंपरिक मूर्तियां और कलात्मक वस्तुएं यहां की अद्भुत शिल्पकला का उदाहरण हैं। इसी प्रकार लकड़ी और बांस से निर्मित हस्तशिल्प ग्रामीण और जनजातीय कारीगरों की रचनात्मकता को दर्शाते हैं। मिट्टी के बर्तन, लोक चित्रकला, पारंपरिक आभूषण और गोदना कला भी प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। गोदना केवल सौंदर्य का

माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक विश्वासों का प्रतीक माना जाता है।

छत्तीसगढ़ के त्योहार यहां की लोक संस्कृति को और अधिक जीवंत बनाते हैं। यहां के अधिकांश पर्व कृषि, प्रकृति और लोक आस्था से जुड़े हुए हैं। हरेली किसानों का प्रमुख त्योहार है, जिसमें कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। पोला पर्व बैलों और कृषि संस्कृति के सम्मान का प्रतीक है। तीजा महिलाओं का प्रमुख पर्व है, जो परिवार की सुख-समृद्धि और दांपत्य-जीवन की मंगलकामना के लिए मनाया जाता है। छेरछेरा त्योहार सामाजिक समरसता और अन्नदान की परंपरा को दर्शाता है। इन पर्वों के दौरान लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक व्यंजन पूरे वातावरण को उत्सवमय बना देते हैं।

बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपराओं का सबसे भव्य उदाहरण माना जाता है। यह देश का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा उत्सव है, जो लगभग 75 दिनों तक मनाया जाता है। यह पर्व शक्ति की आराधना, जनजातीय परंपराओं और सामाजिक सहभागिता का अनूठा संगम है। मां दंतेश्वरी की पूजा के साथ निकलने वाली विशाल रथयात्रा यहां की सांस्कृतिक आस्था का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है।

छत्तीसगढ़ का खान-पान भी यहां की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। चावल यहां का प्रमुख भोजन है। फरा, चीला, अंगाकर रोटी, ठेठरी-खुरमी, देहरौरी और बोरे बासी जैसे पारंपरिक व्यंजन प्रदेश की विशेष पहचान हैं। बोरे बासी को श्रमशील जीवनशैली और ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। प्राकृतिक और सादगीपूर्ण भोजन यहां के लोगों के स्वास्थ्य और जीवनशैली से गहराई से जुड़ा हुआ है।

प्रदेश में स्थित प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक स्थल और प्राकृतिक धरोहरें भी इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करती हैं। बम्लेश्वरी मंदिर, सिरपुर, बत्तीसा मंदिर और चित्रकोट जलप्रपात जैसे स्थल प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को और अधिक समृद्ध बनाते हैं।

**दीपक कुमार यादव,
पीआरओ पर्यटन एवं संस्कृति
विभाग छत्तीसगढ़ शासन**

घने जंगलों और नदी-नालों को पार कर स्वास्थ्य दूतों ने बचाई दो मासूमों की जान

सुकमा जिले के के दुर्गम अंचलों में जहाँ भूगोल भी कदम-कदम पर परीक्षा लेता है, वहाँ सुकमा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कर्तव्यनिष्ठा की एक बेमिसाल इबारत लिखी है। 'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान' के तहत दूरस्थ पहुँचविहीन ग्राम दुरभा पहुँची टीम ने दो मासूमों 5 वर्षीय माड़वी नन्दे और 4 वर्षीय माड़वी सुमड़ी को नई जिंदगी दी। मलेरिया, गंभीर कुपोषण और शरीर में मात्र 2 से 3 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ कमजोर इन बच्चियों के लिए प्रशासन की यह सक्रियता किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई।

कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के 'स्वस्थ बस्तर' के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। घने जंगलों, नदी और नालों को पार कर जब टीम दुरभा पहुँची, तो बच्चों की हालत देख उन्हें तत्काल अस्पताल पहुँचाने का निर्णय लिया गया। दुर्गम रास्तों पर मीलों का सफर पैदल तय कर बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 96 किलोमीटर दूर जिला चिकित्सालय सुकमा पहुँचाया गया। प्रशासन की इस संवेदनशीलता ने साबित कर दिया कि सरकार की नजरें बस्तर के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति पर भी हैं।

जिला अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने युद्ध स्तर पर बच्चों का इलाज शुरू किया। एनीमिया और मलेरिया से जूझ रहे इन बच्चों को न केवल खून चढ़ाया गया, बल्कि मलेरिया का पूरा कोर्स और गहन चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई गई। पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में हुए इस निःशुल्क उपचार का परिणाम सुखद रहा। कुछ ही दिनों में बच्चों का हीमोग्लोबिन स्तर 9 ग्राम के पार पहुँच गया और उनके मुरझाए चेहरों पर मुस्कान लौट आई। इस दौरान बच्चों के परिजनों को पोषण, स्वच्छता और बच्चों के मानसिक विकास के लिए विशेष परामर्श भी दिया गया ताकि भविष्य में उन्हें ऐसी चुनौतियों का



सामना न करना पड़े।

इलाज के बाद बच्चों को सकुशल उनके गाँव तक वापस पहुँचाया गया। कलेक्टर श्री अमित कुमार के अनुसार, यह मिशन केवल उपचार तक सीमित नहीं था, बल्कि बच्चों को शासन की अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु आवश्यक दस्तावेज भी तैयार किए गए। आज दुरभा गाँव में लौट आई इन मासूमों की खिलखिलाहट स्वास्थ्य विभाग के उन सफल प्रयासों की गूँज है, जो दुर्गम पहाड़ों और घने जंगलों को लांघकर जन-जन तक पहुँच रहे हैं।

मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत सुकमा जिले में कुल 2,93,386 लोगों के स्वास्थ्य जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से आज दिनांक तक 1,74,770 लोगों की स्वास्थ्य जांच एवं उपचार किया जा चुका है। अभियान के दौरान लगभग 5,240 मरीजों को मोतियाबिंद, मलेरिया, कुष्ठ, टीबी, खून की कमी, उच्च जोखिम गर्भवती महिला, कुपोषित बच्चे, बीपी एवं शुगर जैसी बीमारियों के लक्षणों के आधार पर चिन्हांकित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला अस्पताल में बेहतर उपचार हेतु रेफर किया गया है।

बाल विवाह के खिलाफ निर्णायक लड़ाई



छत्तीसगढ़ में बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान को केंद्र में रखकर शुरू किया गया बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अब सामाजिक बदलाव की बड़ी मिसाल बनती जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस अभियान को केवल सरकारी योजना तक सीमित न रखते हुए जनभागीदारी का व्यापक आंदोलन बना दिया है। गांव-गांव में जागरूकता और सामाजिक सहभागिता के जरिए बाल विवाह जैसी कुरीति पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में लगातार ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। 10 मार्च 2024 से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ बाल विवाह रोकना नहीं, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना भी है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि, शिक्षक, मितानिनें और महिला स्व-सहायता समूह लगातार जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि अभियान अब प्रशासनिक कार्यक्रम से आगे बढ़कर सामाजिक चेतना का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2028-29 तक पूरे छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। चरणबद्ध योजना के तहत 2025-26 तक 40 प्रतिशत, 2026-27 तक 60 प्रतिशत, 2027-28 तक 80 प्रतिशत और 2028-29 तक सभी ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने की तैयारी है। अभियान की प्रगति भी उत्साहजनक रही है।

31 मार्च 2026 तक राज्य की 11 हजार 693 ग्राम पंचायतों में से 7 हजार 498 पंचायतें बाल विवाह मुक्त

घोषित की जा चुकी हैं, जो कुल पंचायतों का लगभग 64 प्रतिशत है। वहीं 196 नगरीय निकायों में से 85 निकाय इस श्रेणी में शामिल हो चुके हैं।

राज्य के बालोद जिले ने इस दिशा में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए खुद को पूर्णतः बाल विवाह मुक्त घोषित कराया है। प्रशासन और समाज के संयुक्त प्रयासों से मिली यह सफलता अब दूसरे जिलों के लिए प्रेरणा बन रही है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव शिक्षित और आत्मनिर्भर बेटियां ही होंगी। इसी सोच के साथ सरकार बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू कर रही है।

कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं की पढ़ाई प्रभावित होती है, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ते हैं और उनके भविष्य की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। यही कारण है कि अभियान के तहत किशोरियों और अभिभावकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है ताकि समाज में स्थायी बदलाव लाया जा सके।

पंचायत आधारित जनभागीदारी, सतत निगरानी और सामाजिक जागरूकता के प्रभावी मॉडल के कारण बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान अब राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। राज्य सरकार का यह प्रयास केवल एक सामाजिक कुरीति को समाप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण का व्यापक संकल्प बनकर उभर रहा है।

डॉ. दानेश्वरी सम्भाकर,
उप संचालक, जनसंपर्क संचालनालय

पीएम मोदी की अपील

ईंधन कम जलाएं, 'वर्क फ्रॉम होम' अपनाएं

वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए नागरिकों और व्यवसायों से एक विशेष अपील की है। तेलंगाना में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और उर्वरकों की कीमतों में आए भारी उछाल के कारण देश के आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, जिसे कम करने के लिए जनभागीदारी अनिवार्य है।

उन्होंने सुझाव दिया कि नागरिक निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करें और कारपूलिंग जैसे विकल्पों को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के हित में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और रेलवे की पार्सल सेवाओं का अधिकतम उपयोग करने पर भी जोर दिया।

संकट के समाधान के रूप में पीएम मोदी ने कोरोना काल के अनुभवों को याद दिलाते हुए कंपनियों और कर्मचारियों से 'वर्क-फ्रॉम-होम' की संस्कृति को फिर से जीवित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों, वर्चुअल मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने महामारी के दौरान हमारी कार्यक्षमता को बनाए रखा था, और आज ऊर्जा खपत को घटाने के लिए इन आदतों को फिर से अपनाने का सही समय है।

इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए देशवासियों से अगले एक साल तक सोने की खरीदारी और विदेश यात्राओं को टालने का अनुरोध किया ताकि विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके।

उन्होंने घरेलू आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए खाद्य तेल के उपभोग में कटौती करने, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर प्राकृतिक खेती को अपनाने और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की।

हालांकि, प्रधानमंत्री के इन सुझावों पर राजनीतिक



ग्लोबल संकट में

PM मोदी की अपील



प्रधानमंत्री ने **ईंधन की खपत** को लेकर **तुरंत संयम** बरतने को कहा।



PM ने कहा कि दुनिया भर में **पेट्रोल-डीजल** बहुत **महंगे** हो गए हैं।



पेट्रोल-डीजल पर खर्च होने वाला **विदेशी मुद्रा भंडार बचाना** चाहिए।



मेट्रो रेल, कारपूलिंग, EV और रेलवे सेवाओं के इस्तेमाल की अपील।



नागरिकों से एक साल तक **सोना नहीं खरीदने** का आग्रह भी किया।



सप्लाई चेन पर दबाव होने से उपायों के बावजूद मुश्किलें बढ़ती हैं।



वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल बैठकों की व्यवस्था फिट से अपनाई जाए।



विदेशी मुद्रा बचाने के लिए **विदेश यात्राएं स्थगित** करने की अपील।



केमिकल फर्टिलाइजर और खाद्य तेल का इस्तेमाल घटाने की अपील।



प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो

घमासान भी शुरू हो गया है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा पर कोई ठोस नीति बनाने के बजाय अपनी विफलताओं का बोझ आम जनता पर डाल रहे हैं और उन्हें असुविधा की ओर धकेल रहे हैं। विपक्ष ने इसे एक संभावित आर्थिक संकट की आहट बताते हुए सरकार की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

‘मुख्यमंत्री साय ने बरगद पेड़ के नीचे लगाई चौपाल, सुनी ग्रामीणों की समस्याएं’

‘कमरौद में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद, योजनाओं की जमीनी स्थिति का लिया फीडबैक’



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार-2026 के अंतर्गत महासमुंद जिले के विकासखंड बागबाहरा स्थित ग्राम कमरौद पहुंचकर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति की जानकारी ली। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

बरगद के पेड़ की छांव में आयोजित चौपाल में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से आत्मीय संवाद करते हुए कहा कि सरकार गांव-गांव पहुंचकर यह सुनिश्चित कर रही है कि लोगों को राशन, बिजली, प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन और प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाकर समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे अब तक प्रदेश के 16 जिलों का दौरा कर लोगों से सीधे संवाद कर चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं से महतारी वंदन योजना की जानकारी ली, जिस पर महिलाओं ने बताया कि उन्हें नियमित रूप से राशि मिल रही है। ग्राम की देव कुमारी साहू ने बताया कि वह योजना से मिलने वाली राशि अपनी बेटी के भविष्य के लिए बचा रही हैं।

चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने पांचवीं कक्षा के छात्र पूर्वाश साहू से मुस्कराते हुए पूछा कि ‘सेल्फी लेंगे क्या?’ जिसके बाद छात्र ने उत्साहपूर्वक मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली।

यह आत्मीय क्षण चौपाल का विशेष आकर्षण बना

मुख्यमंत्री ने बिजली बिल समाधान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा पंचायत स्तर पर संचालित अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और अतिरिक्त 10 लाख आवासों का निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर नागरिक सेवाओं की पहुंच बढ़ाने



के लिए अब तक लगभग 6000 अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार शीघ्र ही ऑनलाइन शिकायत समाधान व्यवस्था शुरू करने जा रही है, जिसके माध्यम से नागरिक घर बैठे मोबाइल फोन से अपनी समस्याएं दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी प्रारंभ किया जाएगा।

किसानों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने वैश्विक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही।

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरपुर बैराज तथा सिकासेर से कोडार परियोजना महासमुंद जिले के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उल्लेखनीय है कि जिले में सिंचाई क्षमता विस्तार के लिए सिकासेर बांध (गरियाबंद) से शहीद वीर नारायण सिंह जलाशय कोडार तक पानी पहुंचाने की लगभग 3200 करोड़ रुपये की परियोजना पर कार्य किया जा रहा है।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि सरकार गांव-गांव पहुंचकर जनता की बात सुन रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शी और जनहित में कार्य करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना और अन्य योजनाओं से प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बस्तर जैसे क्षेत्रों में जहां पहले हिंसा का माहौल था, वहां अब खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित हो रही हैं।

चौपाल के दौरान ग्राम की लता साहिस ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना तथा गैस सिलेंडर का लाभ मिला है। वहीं मधु साहू ने मछली पालन से जुड़ाव और गर्मी के दौरान पानी की समस्या बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने सोलर आधारित बोर

सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बिहान योजना से जुड़ी परी साहू ने बताया कि स्व-सहायता समूह से जुड़कर वे आत्मनिर्भर बनी हैं और अब फैंसी एवं किराना दुकान संचालित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद वे 'लखपति दीदी' कहलाने लगी हैं।

ग्रामीण मोहन कुलदीप ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का अनुभव साझा करते हुए बताया कि दिसंबर 2025 में सोलर पैनल लगवाने पर उन्हें एक लाख आठ हजार रुपये की सब्सिडी मिली और पहले जहां उनका बिजली बिल लगभग 3500 रुपये आता था, अब शून्य हो गया है। मुख्यमंत्री ने उपस्थित ग्रामीणों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

‘दिव्यांग हितग्राहियों के चेहरे पर खिली मुस्कान’

चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने तीन दिव्यांग हितग्राहियों को सहायक उपकरण प्रदान किए। भारती मारकण्डेय को व्हीलचेयर तथा रवि कुमार पटेल और यादराम साहू को ट्रायसिकल प्रदान की गई। हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उनके दैनिक जीवन और आवागमन में काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के जीवन को सहज, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा अधिकारियों को जरूरतमंद हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से पहुंचाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मातृशक्ति के लिए सर्वसुविधायुक्त भवन निर्माण की घोषणा की, जहां सामाजिक, सांस्कृतिक एवं स्व-सहायता समूहों की गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कमरौद से चरोदा तक लगभग चार किलोमीटर सड़क निर्माण तथा ग्राम में मुक्ति धाम निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं से ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा गया और ग्रामीणों ने उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बलौदाबाजार जिले के करहीबाजार में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य सरकार को गांव-गांव तक पहुंचाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में समाधान शिविर में पहुंचे ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार यह जानने के लिए गांवों तक पहुंच रही है कि लोगों को पानी, बिजली, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाएं समय पर मिल रही हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि रायपुर में बैठकर ग्रामीणों की समस्याओं को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, इसलिए पूरी सरकार गांवों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद कर रही है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक अनेक स्थानों पर शिविर संपन्न हो चुके हैं तथा आगामी दिनों में भी शिविरों का आयोजन जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने





प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को प्राथमिकता के साथ पूरा किया है। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और दो वर्षों का बकाया बोनस भी दिया गया है।

उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस योजना से महिलाएं बच्चों की पढ़ाई, घरेलू जरूरतों और छोटे व्यवसायों के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने 'लखपति दीदी' अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं और आगे करोड़पति दीदी बनने की दिशा में बढ़ रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार कर रही है। प्रदेश की 6000 से अधिक पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र स्थापित

किए गए हैं, जहां लोगों को प्रमाण पत्र, राजस्व रिकॉर्ड, बैंकिंग और अन्य सेवाएं गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अब रजिस्ट्री के साथ तत्काल नामांतरण की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे लोगों को अनावश्यक परेशानी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कही कि सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री हेलपलाइन शुरू करने जा रही है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी समस्याएं ऑनलाइन और टोल फ्री नंबर के जरिए दर्ज करा सकेंगे तथा समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया तथा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं और स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता की सुविधा और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव एवं जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित थे।

सुशासन तिहार : गांव-गांव पहुंच रही शासन की योजनाएं



राज्य शासन द्वारा सुशासन को जन-जन तक पहुंचाने तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत लगातार जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के साथ-साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जा रही है।

इसी क्रम में जांजगीर-चांपा जिले के जनपद पंचायत अकलतरा अंतर्गत ग्राम पंचायत कापन में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नागरिकों ने अपनी मांगों, समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

शिविर में राशन कार्ड, श्रम कार्ड, रोजगार कार्ड, आइस बॉक्स, जाल सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री एवं चेक वितरित किए गए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित आवासों की चाबियां भी हितग्राहियों को सौंपी गईं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोदभराई एवं शिशुओं का अन्नप्राशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभाग द्वारा पूरक पोषण आहार, बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं बाल विवाह रोकथाम के संबंध में जागरूकता भी प्रदान की गई। जनपद पंचायत अकलतरा के ग्राम पंचायत कापन में आयोजित शिविर में कुल 924 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 868 मांग एवं 56 शिकायतों से संबंधित आवेदन शामिल हैं।

जिला पंचायत अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी ने कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित होकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं तथा उनका निराकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जा रही है, जिससे पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू, जनपद पंचायत अकलतरा अध्यक्ष शकुन देव अघरिया, जनपद सदस्य शंकर गौतम, ईश्वर साहू, आनंद मिरी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत 26 मई को नगर पंचायत खरौद के नगर पंचायत भवन तथा जनपद पंचायत बलौदा अंतर्गत ग्राम पंचायत खैजा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परिसर में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया जाएगा। नगर पंचायत खरौद में आयोजित शिविर में वार्ड क्रमांक 01 से 15 तक के कुल 15 वार्ड शामिल होंगे। वहीं ग्राम पंचायत खैजा में आयोजित शिविर में खैजा, नवगवां, बेलटुकरी, पंतोरा, हेड़सपुर, बक्सरा, अंगारखार, करमा, कण्डरा, गतवा, केराकछार, बोकरेल, बोकरामुड़ा, परसदा, पुरेना, देवरी, पहरिया, करमंदा, औराईखुर्द, औराईकला, जर्वे-ब, बैजलपुर एवं खोहा सहित कुल 23 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल होंगे।

मिर्जापुर के 'मुन्नाभैया' अब साउथ में दिखाएंगे स्वैग



राम चरण स्टारर फिल्म 'पेद्दी' (Peddi) जब से अनाउंस हुई है, तब से ही काफी चर्चा में है। फिल्म की रिलीज से पहले, मेकर्स यह पक्का कर रहे हैं कि फ्रैंस को लगातार अपडेट मिलते रहें, और वे फिल्म की शूटिंग की दिलचस्प झलक दिखाकर उन्हें उत्साहित कर रहे हैं।

फिल्म से दिव्येंदु की पहली झलक आई सामने

हाल ही में एक एक अपडेट में मेकर्स ने अब एक्टर दिव्येंदु को 'रामबुज्जी' के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है। अपने सोशल मीडिया पर, Peddi के मेकर्स ने सेट से Rambujji, यानी Divyenndu की एक रोमांचक झलक शेयर की।

इस दिन सामने आएगा ट्रेलर

कैप्शन में लिखा था, 'Rambujji को Hi कहिए। ब्रह्म शुरू होने वाला है! दिव्येंदु को पेद्दी की दुनिया में देखिए। पेद्दी का ट्रेलर 18 मई को आ गया और यह 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पेद्दी के लिए तैयार रहिए'।

पेद्दी की कास्ट

राम चरण की पेद्दी को लेकर लोगों में उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेकर्स फिल्म में राम चरण के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन वाले शानदार पोस्टर और दमदार झलकियां लगातार जारी कर रहे हैं। बुची बाबू सना द्वारा लिखी और निर्देशित 'Peddi' में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं, और उनके साथ शिव राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी नजर आएंगे।

वृद्धि सिनेमाज के बैनर तले वेंकट सतीश किलारू द्वारा निर्मित और मैत्री मूवी मेकर्स के सहयोग से बनी यह फिल्म दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्सुकता जगा रही है। धुरंधर (Dhurandhar) और राजा शिवाजी की शानदार सफलता के बाद, 'Peddi' को उत्तरी भारत (नॉर्थ इंडिया) में Jio Studios द्वारा रिलीज किया जाएगा।

कब रिलीज होगी फिल्म?

इस फिल्म का प्रीमियर 3 जून, 2026 को दुनिया भर में होगा, जिसके बाद 4 जून, 2026 को इसे दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते सलमान

सुपरस्टार सलमान खान ने अपने बॉलीवुड करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों दी हैं। अब उन्होंने फिल्मों के चयन को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। हाल ही में एक बातचीत के दौरान, सलमान ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है।

सलमान ने वैरायटी इंडिया के साथ खुलकर बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ और करियर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस बातचीत का प्रमो शुक्रवार को जारी किया गया, जिसने तुरंत ऑनलाइन प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित किया।

स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते सलमान खान

अभिनेता ने अपनी फिल्म निर्माण प्रक्रिया के बारे में खुलकर खुलासा करके कई लोगों को चौंका दिया, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने पूरे करियर में कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। वीडियो में सलमान को यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'मैंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। मैंने स्क्रिप्ट लिखी हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी पढ़ा नहीं।' बता दें कि इससे पहले भी सलमान ने हिंट दिया था कि वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बजाया फिल्म का पूरी फील, ट्रीटमेंट और कॉमर्शियल अपील अच्छे से समझ लेते हैं।

किसकी महंगी घड़ियां पहनते हैं सलमान?

वीडियो में सलमान खान उन महंगी घड़ियों को

लेकर भी चर्चा करते नजर आए, जिन्हें वह अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों और आयोजनों में पहने हुए दिखाई देते हैं। पिछले कुछ सालों में सुपरस्टार ने कई बार महंगी घड़ियां पहनकर सबका ध्यान खींचा है, जिनमें से कई की कीमत कथित तौर पर 1 करोड़ रुपये से अधिक है। इसी बारे में बात करते हुए सलमान ने हिंदी में कहा, 'आप मुझे घड़ियां पहने हुए देखते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे घड़ियां मेरी हैं। ये मेरे दोस्त की हैं...'

सलमान खान की आने वाली फिल्म

सलमान जल्द ही 'मातृभूमि' में नजर आएंगे, जिसमें बड़े बदल। व किए जा रहे हैं।

मार्च तक इस फिल्म का नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था और खबरों के मुताबिक यह गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुए वास्तविक संघर्ष से प्रेरित थी। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट ने एक नया मोड़ ले लिया है - इसका शीर्षक बदल दिया गया है, चीन और गलवान घाटी के संदर्भ हटा दिए गए हैं, और बताया जा रहा है कि टीम बड़े पैमाने पर रीशूट कर रही है।



भारतीय युवा मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन

एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 17 पदक जीते



एशियाई मुक्केबाजी अंडर-15 और अंडर-17 चैंपियनशिप में भारत का अभियान कुल 17 पदकों (दो स्वर्ण, सात रजत और आठ कांस्य) के साथ समाप्त हुआ जिसमें लड़कियों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। अंडर-17 लड़कियों की टीम ने 12 पदक (दो स्वर्ण, छह रजत और चार कांस्य) जीते, जबकि अंडर-17 लड़कों ने एक रजत और चार कांस्य पदक जोड़े।

राखी (46 किग्रा) ने उज्बेकिस्तान की रुखशोनबोनु अहदोवा के खिलाफ आरएससी (रैफरी द्वारा मुकाबला रोकना) से जीत हासिल कर स्वर्ण पदक जीता, जबकि नव्या (57 किग्रा) ने जापान की सारा कोनो के खिलाफ 4-0 की जीत दर्ज कर दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। खुशी चंद (48 किग्रा) को जापान की अरिसा योशिनागा से 1-4 से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

लक्ष्य फोगाट स्वर्ण से चूके

दीया (63 किग्रा) और हिमांशी (70 किग्रा) ने भी क्रमशः उज्बेकिस्तान की मेहरिमाख किलिचोवा और करीना इल्मुरातोवा से 0-5 से हारने के बाद रजत पदक



जीते। ज्योति (75 किग्रा) कजाखस्तान की डायना नादिरेबेक से 1-4 से हार गई जबकि वंशिका (80 किग्रा) कजाखस्तान की ही झानसाया येरझान से 0-5 से पराजित हो गई। गुरसीरत कौर ने 80 से अधिक किग्रा वर्ग में कड़ी चुनौती पेश की लेकिन उज्बेकिस्तान की सोहिबाखोन खुदोयबेर्दीवा से 2-3 के करीबी अंतर से हार गई। लड़कों के फाइनल में लक्ष्य फोगाट (75 किग्रा) ने उज्बेकिस्तान के मारुफजोन तोशपुलातोव से 0-5 से हारने के बाद रजत पदक के साथ अभियान समाप्त किया।

वैभव सूर्यवंशी ने मिचेल स्टार्क को भी नहीं बख्शा

विराट कोहली और अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ा

अभिषेक शर्मा और विराट कोहली को पछाड़ा

आईपीएल 2026 में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जसप्रीत बुमराह और जोश हेजलवुड जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के बाद अब वैभव के निशाने पर दिल्ली कैपिटल्स के स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आए। मैच के एक ही ओवर में वैभव ने स्टार्क की लाइन-लेंथ बिगाड़ते हुए मैदान के चारों तरफ शॉट खेले और एक नया इतिहास रच दिया।

स्टार्क के ओवर में

मचाया घमासान

पारी के तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क गेंदबाजी के लिए आए लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उनका स्वागत बेहद कड़े अंदाज में किया। ओवर की शुरुआत स्टार्क ने एक वाइड गेंद से की जिसके बाद वैभव ने जोरदार प्रहार किया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई थर्ड मैन बाउंड्री के पार चार रनों के लिए चली गई। स्टार्क ने अगली गेंद यॉर्कर डालने की कोशिश की जो फुल टॉस बन गई जिसपर कोई रन नहीं बना। लेकिन तीसरी गेंद पर वैभव ने स्टार्क की शॉर्ट पिच गेंद को भांपते हुए ऐसा गगनचुंबी पुल शॉट खेला कि गेंद फाइन लेग स्टैंड्स में जा गिरी। शॉट इतना दमदार था कि अंपायर को गेंद बदलने तक का डिब्बा मंगाना पड़ गया था।

इस मुकाबले में लगाए छक्कों की बढ़ती वैभव सूर्यवंशी ने किसी एक आईपीएल सीजन में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वैभव के नाम अब इस सीजन में 43 छक्के हो चुके हैं। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा (42 छक्के) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में उन्होंने श्रेयस अय्यर (39 छक्के) और विराट कोहली (38 छक्के) जैसे दिग्गजों को बहुत पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान पर अपना कब्जा जमा लिया है।

पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने का अनोखा रिकॉर्ड

वैभव ने इस मैच में न सिर्फ छक्कों की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि आईपीएल इतिहास के एक बेहद दुर्लभ और अनोखे एलीट क्लब में

भी अपनी जगह पक्की कर ली। वह एक ही आईपीएल सीजन में तीन बार अपनी पारी की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस सीजन में उनके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के देवदत्त पडिक्कल ने भी यह कारनामा किया है। इससे पहले केवल सुनील नरेन और शाहरुख खान ही एक सीजन में तीन बार पहली गेंद पर छक्का लगाने का कमाल कर पाए थे।



स्वातंत्र बोल

RNI : CHHHIN 2022/86325

www.swatantrabol.com

विदेशी फंडिंग से हो रहा
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण...



छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012

एक बेहद **सख्त** कानून है।
इस कानून में **मृत्युदंड** तक का प्रावधान है।

इस कानून के तहत अपराध है :-

- बच्चों का लैंगिक शोषण करना या करवाना
- लैंगिक शोषण का प्रयास करना या करवाना
- अश्लील साहित्य हेतु बच्चों का उपयोग करना या करवाना

**चाईल्ड हेल्पलाइन
1098**



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा
बाल हित में प्रसारित

- निवेदन -

स्वतंत्र बोल से संबंधित कोई भी झुझाव या शिकायत हो तो आप नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। फोन और ई-मेल पर भी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र से घटित कोई घटना, समाचार, या अन्य कोई गतिविधि जो पत्रिका में प्रकाशन योग्य हो.. तो उससे भी भेज सकते हैं।

छत्तीसगढ़ का सबसे विश्वसनीय हिन्दी मासिक पत्रिका
तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल और न्यूज वेबसाइट को निर्भीक और
जनपक्षीय पत्रकारिता के लिये आर्थिक रूप से सहयोग करें।

बंधन बैंक

बैंक खाता नंबर - 20100031810292
आईएफएससी कोड - BDBL0001958



संपादक स्वतंत्र बोल

डी-317 बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)

97543-74333, bolswatantra@gmail.com



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



सुशासन
तिहार 2026



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सुशासन
तिहार
2026

01 मई
से
10 जून
2026

गाँव-गाँव, द्वार-द्वार
सुशासन की सरकार



जिला स्तर पर लंबित प्रकरणों, जमीन संबंधी मामलों एवं प्रमाण-पत्र से जुड़ी समस्याओं का निराकरण

ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन

समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध समाधान

जन-कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

उद्देश्य

विकास कार्यों को मिलेगी गति

पारदर्शिता और जवाबदेही से 'जनकल्याण' होगा सुनिश्चित

संवाद से संपूर्ण समाधान



छत्तीसगढ़
सहस्र योजना

Visit us : [f](#) [x](#) [@](#) [/ChhattisgarhCMO](#) [f](#) [x](#) [@](#) [/DPRChhattisgarh](#) [www.dprcg.gov.in](#)

RO. No. 13786/21